vkj- ,u- vkb- u- UPHIN/2010/32566 Mkd- i:th;u- l:[;k& SSP/LW/NP-311

अद्भुत समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी साप्ताहिक

हर ख़बर पर पैनी नज़र

o"k Z % 14 vad % 14 y[kuÅ] 'kdokj 14 tqykbZ 2023 l 20 tqykbZ 2023 rd i"B&8 eY; % ,d :i;k

दिल्ली में बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 16 टीम तैनात

नई दिल्ली। दिल्ली में यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की १६ टीम को

तैनात कर दिया गया है और शुक्रवार सुबह तक हालात सुधरने की उम्मीद है। एनडीआरएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी दी। एनडीआरएफ के उप महानिरीक्षक मोहसिन शाहिदी ने यहां संवाददाताओं को बताया कि पूर्वी और उत्तर–पूर्वी दिल्ली में तीन–तीन टीम, दक्षिण–पूर्वी दिल्ली में पांच, मध्य क्षेत्र में चार जबकि राष्ट्रीय राजधानी के शाहदरा इलाके में एक टीम तैनात की गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कुल छह जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। एनडीआरएफ के उप महानिरीक्षक ने कहा, '' चूंकि, पिछले दो दिनों में दिल्ली में न्यूनतम बारिश हुई है, हमें उम्मीद है कि स्थिति अब स्थिर हो जाएगी और कल सुबह तक हालातबेहतर होने की उम्मीद है।'' उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों और दिल्ली तथा उसके आसपास के स्थानों में पिछले चार–पांच दिनों की भारी बारिश के बाद शहर में यमुना नदी के आसपास के निचले इलाकों में पानी भर गया है। एनडीआरएफ ने लगभग १,००० लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाला है और लगभग ३,५०० स्थानीय लोगों को बचाया है। स्वयंसेवक, जिला प्रशासन और पुलिस भी बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं। पानी का स्तर ३.५ लाख क्यूसेक से घटकर ६,३०० क्यूसेक हो गया है और शुक्रवार तक यह और स्थिर हो जाएगा। उन्होंने बताया कि ताजा जानकारी के अनुसार, यमुना २०८.६६ मीटर के स्तर पर बह रही है। मोहसिन शाहिदी ने कहा,''हालांकि, दिल्ली और उत्तराखंड में बारिश का अनुमान है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में स्थिति सामान्य होगी। चिंता की कोई बात नहीं है और हम लोगों से अपील करेंगे कि वे सतर्क रहें और बाढ़ प्रभावित इलाकों के पास न जाएं।'' एनडीआरएफ की सभी टीम के पास नाव, रस्सियां और बचाव के अन्य उपकरण हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय का यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित करने पर रोक लगाने से किया इनकार

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, २०२३ के लिए आवेदन आमंत्रित करने की क ल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह की एकल–न्यायाधीश पीठ ने एक लंबित मामले में विभिन्न सिविल सेवक उम्मीदवारों द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें यूपीएससी द्वारा १० जुलाई को जारी विस्तृत आवेदन पत्र –१ पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने अपने आवेदन में कहा कि यूपीएससी ने मनमाने ढंग से मुख्य परीक्षा के लिए डीएएफ जारी किया, इसलिए प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी की मांग करने वाली अदालत के समक्ष उनकी मुख्य रिट याचिका निरर्थक हो जाती है। आवेदन में कहा गया है कि फॉर्म जारी करके यूपीएससी कानून और न्याय की प्रक्रिया को नष्ट करने और गुप्त तरीके से अपनी मनमानी प्रथाओं को जारी रखने के लिए अनुचित जल्दबाजी दिखा रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि यूपीएससी ने अतीत में भी गैर–अनुपालन, समय बीतने या परिस्थितियों में

बदलाव के कारण निष्फल हो जाने के कारण मामलों को सफलतापूर्वक खारिज कर दिया था। उम्मीदवारों ने १२ जून के प्रेस नोट के खिलाफ एक रिट याचिका में आवेदन दिया था जिसमें कहा गया था कि प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी केवल षसिविल सेवा परीक्षा २०२३ की पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अपलोड की जाएगी। मुख्य याचिका में निकाय को तत्काल प्रभाव से उत्तर कुंजी प्रकाशित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई।

यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र के दूरी निर्धारण में अब कोई दिक्कत नहीं आयेगी, नये ऐप पर फोटो करनी होगी अपलोड

लखनऊ। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में परीक्षा केंद्रों के दूरी निर्धारण में अब कोई दिक्कत नहीं आयेगी। इसके लिए विभाग की तरफ से नया मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। दरअसल, साल २०२३ में हुई यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान निर्धारित केंद्रों में सबसे ज्यादा आपत्ति दूरी को लेकर दर्ज की गई थीं। बताया जा रहा है कि बोर्ड के निर्देश पर मोबाइल एप के जरिये विद्यालयों के बीच की दूरी दर्ज की गई थी, लेकिन एप पर जो दूरी दर्ज हुई थी, हकीकत में वह दूरी काफी ज्यादा हुआ करती थी। इसके अलावा स्कूलों में उपलब्ध कमरों की संख्या, फर्नीचर समेत अन्य जानकारी गलत देना भी शामिल था। इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया है कि साल २०२४ में

आयोजित होने वाली हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के लिए गाइड लाइन जारी कर दी गई हैं। परीक्षा के लिए केंद्र बनाये जाने के लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा की तरफ से सभी जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र भेजा गया है। जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि साल २०२४ की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण के लिए सभी विद्यालयों में मौजूद सुविधाओं की सूचना माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट नचउेच.मकन.पद पर अपलोड करना जरूरी है। इसके लिए वेबसाइट को क्रियाशील कर दिया गया है। इसके अलावा विद्यालय के बीच की दूरी निर्धारित करने के लिए एपीआई युक्त नया ऐप भी बनाया गया है। ऐप में विद्यालय की फोटो अपलोड करनी होगी। इस ऐप का नाम वर्जन–१० बताया जा रहा है। इस ऐप में खास बात यह है कि फोटो अपलोड करते ही लोकेशन परिषद के सर्वर पर अपने आप अपलोड हो जायेगा। जिससे परीक्षा केंद्र के दूरी निर्धारण में कठिनाई नहीं आयेगी।

सीएम योगी ने ५१० अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र, कहा- प. बंगाल पंचायत चुनाव में निर्दोष मारे गये

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री

योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बंगाल में चुनाव के समय हुई हिंसा में निर्दोष मारे गये हैं। वहां भी जिम्मेदार लोकतंत्र का ढिंढोरा पीट रहे हैं। जबकि चुनाव के समय उत्तर प्रदेश में एक भी हिंसा नहीं हुई। बिना किसी जनहानि के यूपी में चुनाव संपन्न हुआ है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा और निकाय चुनाव बिना हिंस के सम्पन्न हुये हैं। उन्होंने कहा यह बदलावा यूपी में ईमानदारी के साथ बीते ६ साल में किये गये कार्यों की वजह से आया है। इस दौरान उन्होंने नियुक्ति पत्र लेने पहुंचे अभ्यर्थियों से कहा कि जिस ईमानदारी के साथ आप की नियुक्ति हुई है। उसी ईमानदारी के साथ काम भी करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बावजूद ५५ हजार नियुक्ति पत्र दिये गये हैं। इन नियुक्तियों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। इस दौरान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित १६६ समीक्षा अधिकारी,सहायक समीक्षा अधिकारी (सचिवालय प्रशासन विभाग), १८३ कनिष्ठ सहायक (परिवहन विभाग) व १२८ कनिष्ठ सहायक (निर्वाचन विभाग) कुलमिलाकर ५१० अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र वितरित किया है।

सम्पादकीय

कुर्सी कुमार की हिटलरशाही

बिहार में भाजपा ने जबरदस्त तरीके से नीतीश कुमार और सरकार के खिलाफ हमलावर है। राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति और तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा ने आज मार्च का आयोजन किया था। यह मार्च गांधी मैदान से विधानसभा की ओर जानी थी। हालांकि, डाकबंगला चौराहे पर ही बवाल जबरदस्त तरीके से मच गया। पुलिस ने खूब लाठियां भांजी। भाजपा का दावा है कि उसके एक कार्यकर्ता की मौत हो गई है जबकि दर्जनों कार्यकर्ता घायल है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि पटना में भाजपा प्रदेश कार्यालय में कई घायलों का इलाज भी किया जा रहा है। भाजपा अब नीतीश कुमार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साध रही है। भाजपा का दावा है कि बिहार में अब लोकतंत्र नहीं, ठोकशतंत्र हो गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश बाबू कान खोलकर सुन लीजिए सम्राट न पहले कभी डरा था और नहीं ही कभी डरेगा। उन्होंने जेपी ह स्पिटल में जाकर पुलिसिया बर्बरता कार्रवाई से घायल भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। आरसीपी सिंह ने ट्वीट कर कहा कि कुर्सी कुमार की हिटलरशाही उजागर हुई और लोकतन्त्र का गला सरेआम घोटा गया। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो दमनकारी चरित्र उजागर हुआ, उससे यही प्रतीत होता है कि नीतीश बाबू शान्ति पूर्वक प्रदर्शन,शांति पूर्वक मार्च जैसी लोकतांत्रिक कार्यकलापों में विश्वास नहीं करते हैं। आज की घटना को देखने के बाद कौन कहेगा कि बिहार के मुख्यमंत्री कभी गाँधी,जेपी,लोहिया के आदर्शों में विश्वास रखते थे? आज की इस शर्मनाक घटना की जितनी निंदा की जाय वो कम है! सुशील कुमार मोदी ने कहा कि एकदम शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, बड़ी संख्या में महिलाएं थीं...कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई पथराव नहीं इसके बावजूद जानबूझकर लाठीचार्ज किया गया है। ये सब नीतीश कुमार के इशारे पर हुआ है। इस पर हम सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह पर लड़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता की मौत की जिम्मेदार, बर्बर नीतीश–तेजस्वी सरकार। उन्होंने कहा कि युवाओं, महिलाओं, किसानों के अधिकारों के लिए बिहार की बर्बर नीतीश–तेजस्वी सरकार के खिलाफ संघर्ष करते हुए भाजपा के महामंत्री, जहानाबाद विजय सिंह ने अपनी आहुति दे दी। नीतीश–तेजस्वी सरकार द्वारा बर्बरता पूर्वक चलवाई गयी लाठियों से भाजपा कार्यकर्ता विजय सिंह की मौत की जिम्मेदार नीतीश सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि जितने भी शिक्षक नेता हैं उनसे बात की जाएगी। जो लोग १० लाख रोजगार मांग रहे हैं वह बताएं कि देश में ऐसा कौन सा राज्य है जहां ३ लाख से अधिक सरकारी नौकरी का विज्ञापन निकाला गया हो। उन्होंने कहा कि हम अपने शासनकाल में १० लाख पूरा करे लेंगे, लेकिन वे (भाजपा) २ करोड़ का हिसाब दें। यहां १८ साल तक सरकार में कौन था? महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नौकरी निकाली गई।

निजी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए हुआ एमओयू : मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ। मिशन निरामया के तहत बुधवार को राजधानी के मुख्यमंत्री आवास में मऊ और शामली जिले में निजी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए अनुबंध किया गया। इसके अलावा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों की रेटिंग भी की गई। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा है कि साल २०१७ के पहले प्रदेश में मात्र १२ सरकारी मेडिकल कॉलेज थे और आज यूपी में ४५ जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। इसके अलावा १६ निर्माणाधीन है। जिनमें १४ सरकारी और दो प्राइवेट हैं और आज दो और नए मेडिकल कॉलेज के लिए एमओयू हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की संकल्पना को साकार करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये मेडिकल शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधा गुणवत्तापूर्ण करने में भी महत्वपूर्ण

भूमिका निभाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि मिशन निरामया गत वर्ष में शुरू किया गया था और आज वह देश का ब्रांड बन गया है। वहीं मेडिकल के क्षेत्र में नर्सिंग और पैरामेडिकल बैक बोन होता है। साल २०१७ से पहले मेडिकल शिक्षा की चर्चा तो की गई लेकिन नर्सिंग और पैरामेडिकल को भूल गए। साथ ही कई जगह पर कॉलेज बिना इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकेल्टी के काम कर रहे थे। हमने ६ साल के कार्यकाल में इसे बेहतर करने का काम किया है। इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि अगर कोई भी चिकित्सा संस्थान ने मानक पूरा करता है तो ही उसे संबद्धता और सुविधा दी जाए अगर वे इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकेल्टी, लैब, लाइब्रेरी की सुविधा समेत अन्य मानक पूरा नहीं करते हैं तो ऐसे संस्थानों को बाहर कर दिया जाएगा। हम प्रदेश के किसी युवा के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। मेडिकल के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी संस्थान देंगे।

ड्यूटी से गैरहाजिर चार चिकित्सक बर्खास्त, उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के निर्देश पर हुई कार्रवाई

लखनऊ। ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले चिकित्सकों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। मंगलवार को उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के निर्देश पर चार चिकित्सकों को बर्खास्त कर दिया गया है। मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनिहारी, गाजीपुर में तैनात डॉ. अब्दुल्लाह फैसल, मुख्य चिकित्साधिकारी, मीरजापुर के अधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सींखड़, मीरजापुर में तैनात डॉ. प्रगति शर्मा, मुख्य चिकित्साधिकारी, जौनपुर के अधीन तैनात डॉ. प्रसन्न कुमार सिंह और मुख्य चिकित्साधिकारी, सुल्तानपुर के अधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भदैया, सुल्तानपुर में तैनात डॉ. सन्तोष कुमार वर्मा पर विभागीय कार्रवाई की गई है। लापरवाही और अनुशासनहीनता एवं लम्बे

समय से शासकीय ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का संज्ञान लेते हुए इन चिकित्सकों को बर्खास्त किया गया है। वहीं, जिला चिकित्सालय, कुशीनगर में अव्यवस्थाओं एवं बाहर की दवा लिखे जाने संबंधी प्रकरण को लेकर बृजेश पाठक ने बाहर की औषधियों का परामर्श देने वाले चिकित्सकों के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने के आदेश मुख्य चिकित्साधिकारी कुशीनगर को दे दिये हैं। कार्रवाई के क्रम में कालपी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात चिकित्सा अधीक्षक ड . उदय कुमार का तबादला सामुदायिक केंद्र चुर्खी (बाबई) में कर दिया गया है। वहीं, गोंडा के सीएचसी कटरा बाजार पर तैनात कंप्यूटर आपरेटर अजय यादव पर जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर रुपए लेने के आरोप के मद्देनजर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उक्त कर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

शहीद स्मारक पर राहुल गांधी के समर्थन में जुटे कार्यकर्ता, मौन सत्याग्रह कर जताया विरोध

लखनऊ। पूरे देश में आज जगह–जगह कांग्रेस मौन सत्याग्रह कर रही है। यह मौन सत्याग्रह राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के विरोध में हो रही है। राजधानी

लखनऊ स्थित शहीद स्मारक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय मौन सत्याग्रह शुरू किया है। सुबह करीब १० बजे से शुरू हुआ यह सत्याग्रह शाम पांच बजे तक चला। इस दौरान कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने भी इस सत्याग्रह में हिस्सा लिया। राहुल गांधी के समर्थन में शुरू हुये इस मौन सत्याग्रह में भारी तादात में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुये। जिसमें प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी, राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी, अंशु अवस्थी, सचिन रावत समेत अन्य नेता मौजूद रहे। यूपी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं। देश के मौजूदा हालात को देखते हुये कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और आम लोग उनके साथ खड़े हैं। राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए मोदी सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते रहे हैं। इसी के चलते उनकी लोकसभा की सदस्यता छीनी गई है।

वृहद् पौधरोपण अभियान के तहत लोक निर्माण विभाग १२.६३ लाख पौधारोपण कराएगा : जितिन प्रसाद

लखनऊ। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने वृहद् पौधारोपण अभियान २०२३ की तैयारी को लेकर बुधवार को पीडब्ल्यूडी मुख्यालय सभागार में समीक्षा बैठक कर पौधरोपण की तैयारियों की जानकारी ली और अवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पौधरोपण अभियान की समस्त तैयारियां समय से पूरी कर ली जाय, इसे महोत्सव की रूप में मनाया जाना है। पौधरोपण अभियान में लोक निर्माण विभाग को अहम जिम्मेदारी दी गई है। पौधरोपण अभियान के तहत विभाग के लिए निर्धारित कुल १२.६३ लाख पौधरोपण के लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत वृक्षारोपण कराया जाए। पौधरोपण अभियान के तहत सड़कों की भविष्य की प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए पौधों को लगाया जाए, जिससे सड़कों के चौड़ीकरण या अन्य निर्माण कार्यों के दौरान कम से कम पेड़ों को काटने की आवश्यकता पड़े। मंत्री ने क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को निर्देशित

करते हुए कहा कि पौधरोपण अभियान के तहत केवल पौधों को लगा देना ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उन पौधों के रखरखाव के लिए पुख्ता इंतजाम किया जाए। पौधों को सुरक्षित रखने के लिए ट्री गार्ड लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करवाई जाए। क्षेत्र विशेष की भौगोलिक विशेषता के अनुसार ही पौधरोपण का कार्य करवाया जाए। पौधरोपण अभियान के तहत फल,फूलदार पौधों के रोपण पर विशेष फोकस किया जाए। बैठक में प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग अजय चौहान, विशेष सचिव लोक निर्माण विभाग केपी सिंह, प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष अरविंद कुमार (जैन), प्रमुख अभियंता ग्रामीण सड़क विनोद कुमार श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता संजय कुमार श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता अशोक अग्रवाल, मुख्य अभियंता परवेज अहमद, समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता (वीडियो क न्फरेंसिंग के माध्यम से) सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

एनसीईआरटी पुस्तकों को लेकर निर्देश जारी, सस्ते दामों पर होंगी उपलब्ध

लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शैक्षणिक सत्र २०२३–२४ में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई में उपयोग होने वाली पाठ्यपुस्तकों को लेकर सभी विद्यालयों को निर्देश जारी किए हैं। साथ ही परिषद में पाठयपुस्तकों के मुद्रण और वितरण के लिए तीन मुद्रकों को अधिंत किया है और सस्ती दर पुस्तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण एनसीईआरटी और न न एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता कराई जाएगी और इन्हीं पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से अध्ययन–अध्यापन कराया जायेगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देशानुसार अब हाईस्कूल इंटरमीडिएट की पुस्तकें सस्ते दामों में मिलेंगी। जिसमें हाई स्कूल स्तर (कक्षा–६ एवं १०) की अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और इण्टरमीडिएट स्तर (कक्षा–११ एवं १२) की अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, लेखाशास्त्र, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान समेत कुल ३६ विषयों के अन्तर्गत जाने वाली

७० एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों और कक्षा ६ से १२ तक की हिन्दी, संस्कृत एवं उर्दू विषयों की १२ नॉन एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकें शामिल है। ये सभी पुस्तकें अब प्रदेश के समस्त राजकीय सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को सस्ते दर में उपलब्ध हो रही है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा परिषद ने एनसीईआरटी और नॉन एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों की निर्धारित मूल्य सूची जारी की है। साथ ही निर्देशित किया है कि पुस्तकों का क पीराइट माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश में निहित है। ऐसे में इन पुस्तकों की पाइरेसी/डुप्लीकेसी किसी भी दशा में न हो पाए। इसको लेकर परिषद ने विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देशानुसार अगर जिले में एनसीईआरटी और नॉन एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों की अनुपलब्धता या कमी की स्थिति बनती है तो संबंधित अधिंत मुद्रक या वितरक से संपर्क करके पुस्तकों की उपलब्धता को पूरा किया जाए। इसके अलावा एक निश्चित अवधि तक विद्यालयों में शिविर लगाकर एनसीईआरटी और नॉन एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों को मुहैया कराया जाए। साथ ही इन पुस्तकों के अलावा किसी छात्र से अन्य पुस्तकें खरीदने के लिए बाध्य न किया जाए।

अधिकारी नियमों का पालन करते हुए कार्यों को त्वरित रूप से करें पूरा : राज्यपाल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंगलवार को अधिकारियों को नसीहत दी कि वे अपनी जिम्मेदारी समझें और सेवा भाव से जनता की सेवा करें। उन्होंने उन्हें नियमों का पालन करते हुए कार्यों को त्वरित रूप से पूरा करने को कहा। पटेल ने राजभवन में शिष्टाचार भेंट करने आये भारतीय प्रशासनिक सेवा २०२२ बैच के १४ परिवीक्षाधीन अधिकारियों को सम्बोधित करते हुये कहा, ''आज सरकार तथा आम आदमी की आपसे बहुत अपेक्षायें हैं, आपका दायित्व है कि लोगों का कार्य त्वरित रूप से निस्तारित करें ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़ें।'' उन्होंने कहा, श्श्अधिकारी से ज्यादा सर्वप्रथम आप सभी अच्छे इंसान बनकर जनता के बीच एक जीवंत उदाहरण बनकर उभरें, ताकि लोगों का विश्वास आपके प्रति दृढ़ हो। यह तभी संभव हो सकता है जब आपके अन्दर एक सकारात्मक सोच, सजृनात्मकता तथा मानवता हो, तभी आप लोगों के दिलों में अपना स्थान बना पायेंगे।'' पटेल ने कहा, ''किसी भी फरियादी की समस्या को दूर करने के लिए आप को स्वयं उस समस्या को महसूस करना होगा, तभी आप पीड़ित व्यक्ति को राहत दे पायेंगे।'' राज्यपाल ने प्रत्येक कार्य कानून के दायरे में करने तथा नियम का पालन करते हुए त्वरित रूप से

पूरा करने का सुझाव दिया। राजभवन से मंगलवार को जारी बयान के अनुसार फाइल पर बार–बार आपत्ति लगाने की प्रवृत्ति पर तीखी प्रतिक्रिया करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारियों का यह दायित्व होना चाहिए कि प्रस्तुत फाइल को पूरी तरह से पढ़कर उसके हर पहलू को समझकर त्वरित निर्णय लें और व्यक्ति को समाधान देने का प्रयास करें, ताकि सम्बन्धित व्यक्ति विभाग का अनावश्यक चक्कर न लगाये। राज्यपाल का स्वागत प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा तुलसी का पौधा भेंट कर किया गया।

लखनऊ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की वर्दी में घूम रहे फर्जी युवक-युवती पकड़े गये

लखनऊ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के फर्जी पहचान पत्र के सहारे चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ के अराइवल सिटी साइड एरिया में सीआईएसएफ के सहायक उपनिरीक्षक पद की वर्दी पहन कर संदिग्ध घूम रहे एक युवक और युवती को सीआईएसएफ जवानों ने धर दबोचा। बाद में

जांच पड़ताल के बाद दोनों को सरोजनीनगर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर उनसे पूछताछ कर रही है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ के उप निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह के मुताबिक शाम करीब ७रू३० बजे सीआईएसएफ के सहायक उप निरीक्षक पद की वर्दी पहन कर एक संदिग्ध व्यक्ति एक लड़की के साथ एयरपोर्ट के अराइवल सिटी साइड एरिया में लेकर घूम रहा था। संदेह होने पर जब सीआईएसफ स्टाफ ने उनसे पूछताछ की, तो पता चला कि दोनों व्यक्ति सीआईएसएफ में कार्यरत नहीं है। आनन फानन इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दी गई। इसके बाद हुई पूछताछ में पता चला कि पकड़ा गया युवक गोरखपुर के बनगंवा का रहने वाला इंद्रेश मौर्या, जबकि रायबरेली के कुंदनगंज स्थित पहराखेड़ा निवासी युवती सोनी है। दोनों से तलाशी ली गई तो उनके पास सीआईएसएफ का कूट रचित पहचान पत्र और बीसीएएस का टेंपरेरी एयरपोर्ट एंट्री परमिट मिला। बाद में अधिकारियों ने बीसीएएस से कंफर्म किया तो पता चला कि वह सब कूट रचित है। फिलहाल सीआईएसएफ ने दोनों को हिरासत में लेकर सरोजनीनगर पुलिस के हवाले कर दिया। सरोजनीनगरपुलिस सीआईएसएफ उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह की तहरीर पर गुरुवार को रिपोर्ट दर्ज कर दोनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस पूछताछ में इंद्रेश मौर्य ने बताया कि वह लोगों को अपनी बातों में फंसाकर सीआईएसएफ में नौकरी लगवाने के नाम पर उनके पैसे लेता था। इसके लिए उसने सीआईएसएफ, अडानी एयरपोर्ट और अन्य कई मेल आईडी को गूगल करके उनकी फेक ईमेल आईडी बना रखी है। उसने बताया कि वह फोटो एडिटर एप से लोगों के फोटो व नाम एडिट करके फर्जी ज इनिंग लेटर बनाकर उन लोगों को फेक ईमेल आईडी से भेज देता था। फर्जी वर्दी के पूछने पर उसने बताया कि यह वर्दी लखनऊ के सदर बाजार से खरीदी थी और लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचकर अपने घर वालों को वीडियो क ल कर वर्दी दिखा रहा था। जिससे उन्हें विश्वास हो जाए कि वह सीआइएसएफ में नौकरी कर रहा है। पूछताछ में बताया कि सोनी भी उसके काम में सहयोग करती थी। उसका बनाया ही टेंपरेरी पास उसके पास था। पूछताछ में इंद्रेश ने बताया कि सीआईएसएफ जवान के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने के लिए सीआईएसफ के नेट के माध्यम से आईडी कार्ड का प्रोफार्मा देखकर उसने कूटरचित आईडी कार्ड बनाया था। फिलहाल पुलिस ने इंद्रेश मौर्य और सोनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

मेगा ई-ऑक्शन के जरिए ७७ प्लॉट्स की हुई नीलामी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने की दिशा में प्रयासरत योगी सरकार ने गुरुवार को एक और मजबूत कदम बढ़ाते हुए मेगा ई–ऑक्शन के माध्यम से निवेशकों को आकर्षित किया। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) द्वारा आयोजित इस मेगा ई ऑक्शन के माध्यम से सरकार ने ७७ प्लॉट्स की नीलामी प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान की। यह संख्या मेगा ई–ऑक्शन के लिए रखे गए कुल १७६ प्लॉट्स की लगभग आधी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, एसबीआई के पोर्टल पर हुए इस मेगा ई–ऑक्शन में प्रत्येक प्लॉट के लिए १० से १५ बिड हासिल हुईं और उच्चतम बिड को मंजूरी प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि जिन ७७ प्लॉट्स की बिड मंजूर हुई है, उनमें ७६ इंडस्ट्रियल हैं और एक कॉमर्शियल। वहीं, बिड के लिए तय कुल १७६ प्लॉट्स में १५४ इंडस्ट्रियल थे तो बाकी २२ कॉमर्शियल प्लॉट्स थे। यूपीसीडा द्वारा नीलामी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई। पूरी प्रक्रिया ३ घंटे तक चली, जिसमे ७७ प्लॉट्स के लिए बिड फाइनल हो गई। सभी प्लॉट्स के लिए निवेशकों के बीच काफी प्रतिस्पर्धा रही और रिजर्व प्राइस की तुलना में अधिकतम बोली लगाने वाले को प्राथमिकता दी गई। मेगा ई ऑक्शन के लिए यूपीसीडा द्वारा लखनऊ, कानपुर, ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी, अयोध्या, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, बरेली, गोरखपुर व अलीगढ़ जैसे स्थानों पर इंडस्ट्रियल प्लॉट्स उपलब्ध कराए गए हैं। इस मेगा ई–ऑक्शन में कुल मिलाकर १५४ इंडस्ट्रियल, ३ ग्रुप हाउसिंग, एक नर्सिंग होम, एक वेइंग ब्रिज, ८ वेयरहाउस के लिए प्लॉट्स और फ्लैटेड फैक्टरी में १० रेंटेड हॉल रखे गए थे। इन सभी प्रस्तावित प्लॉट्स व रेंटेड हॉल की रिजर्व प्राइसिंग भी तय की गई थी। इसी के आधार पर बिडिंग प्रक्रिया के दौरान बोली लगाने की गतिविधि को अंजाम दिया गया।

भाजपा को टमाटर का ‘लाल’ रंग देखते ही समाजवादियों की याद आती है : अखिलेश

लखनऊ । समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने टमाटर की कीमत में बढ़ोतरी के बीच राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर मंगलवार को तंज किया कि भाजपा को टमाटर का लाल रंग देखते ही समाजवादियों की याद आती है। यादव ने ट्वीट किया, ‘‘भाजपा टमाटर को देखकर इसलिए परेशान है क्योंकि टमाटर का रंग ‘लाल’ होता है और लाल देखते ही उन्हें (भाजपा) समाजवादियों की याद आती है।’’ अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें वाराणसी के टमाटर मामले को लेकर राजनीतिक विश्लेषण किया गया है। सपा प्रमुख के ट्वीट के कुछ ही घंटों बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, ‘‘उत्तर प्रदेश में सपा का २०२४ में खाता खुलना मुश्किल है।’’ केशव प्रसाद मौर्य ने इस ट्वीट में हैशटैग किया श्दकहो दिल से, नरेन्द्र मोदी जी फिर से।श्‍ इसके पहले अखिलेश यादव के ट्वीट पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक से कहा कि रंगों की सियासत करने वाले लोगों को हर चीज में राजनीति दिखती है और

वे उसी चश्मे से देखते हैं। सपा के बारे में लोगों की धारणा और कहावत सुनाते हुए विजय बहादुर पाठक ने कहा, ‘‘जिस गाड़ी पर सपा का झंडा—उस पर बैठा गुंडा, जैसी कहावत अभी भी लोग दोहराते हैं।’’ हाल में वस्तुओं की कीमतों में हुई वृद्धि को लेकर सपा केंद्र और राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर निशाना साध रही है। वाराणसी में गत दिनों समाजवादी पार्टी (सपा) के एक कार्यकर्ता द्वारा महंगे टमाटर की सुरक्षा के लिए दो ‘बाउंसर’ तैनात करने के मामले में पुलिस ने एक सब्जी विक्रेता और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है। वाराणसी के लंका थाना प्रभारी अश्विनी पांडेय ने सोमवार को बताया था कि एक वीडियो में खुद को दुकान का मालिक दिखाने वाला सपा नेता अजय फौजी फरार है। पुलिस ने बताया कि सब्जी विक्रेता जगनारायण यादव और उसके बेटे विकास यादव को रविवार को ‘मानहानि’ के मामले में गिरफ्तार किया गया है। वीडियो में सपा कार्यकर्ता ने दावा किया था कि उसने टमाटर की कीमतों का मोल भाव करने के दौरान ग्राहकों की ‘उग्रता’ से बचने के लिए दो बाउंसर तैनात किए हैं। फौजी ने हाल में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन पर टमाटर की ऑोति वाला केक काटा था और टमाटर बांटे थे।

दिल्ली में बारिश-बाढ़ से २०० करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित : सीटीआई

नई दिल्ली। दिल्ली में बारिश और बाढ़ से लगभग २०० करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित हुआ है। व्यापारियों के संगठन चौम्बर्स अ फ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने बृहस्पतिवार को यह अनुमान जताया। सीटीआई ने यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए कारोबारियों से दूसरे शहरों से व्यापार कुछ दिनों के लिए स्थगित करने की अपील करते हुए कहा कि पुरानी दिल्ली, कश्मीरी गेट, मोरी गेट, म नेस्ट्री मार्केट, चांदनी चौक, जामा मस्जिद, भागीरथ मार्केट, लाजपत राय मार्केट, किनारी बाजार, फतेहपुरी, खारी बावली, नया बाजार के बाजार प्रभावित हुए हैं। सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा, ”हम पुरानी दिल्ली के कारोबारी और बाजार संघों से बाहर से व्यापार कुछ दिनों के लिए रोकने की अपील की है।”कश्मीरी गेट मार्केट के अध्यक्ष विनय नारंग ने कहा कि तीन—चार दिन बारिश के कारण ५० करोड़ रुपये से ज्यादा के नुकसान की आशंका है। सीटीआई ने बारिश से लगभग २०० करोड़ रुपये के कारोबार के प्रभावित होने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा, ”यमुना में बढ़ता जलस्तर दिल्ली के बाजारों को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। कारोबार लगभग ठप हो गया है। व्यापारी स्थिति के सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। नजदीकी शहरों से आने वाले

ग्राहकों ने योजना टाल दी है। रेलवे ने पुराने लोहे के पुल से रेल गतिविधियां बंद कर दी हैं, कई ट्रेनों का मार्ग बदल गया है, जबकि कुछ ट्रेनें रद्द भी हुई हैं। अब कारोबारी और खरीदारों ने दिल्ली आने की योजना भी कुछ दिन के लिए टाल दी है।” सीटीआई के अनुसार, दिल्ली में रेवाड़ी, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, मेरठ, सोनीपत, पानीपत, पलवल, बागपत, बड़ौत, मुजफ्फरनगर आदि शहरों से प्रतिदिन दो लाख ग्राहक आते हैं।

कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों की कार्यशाला, नेताओं ने चुनाव में जुटने को कहा

नई दिल्ली। कांग्रेस के नवनिर्वाचित ब्लॉक अध्यक्षों की एक दिवसीय कार्यशाला बृहस्पतिवार को यहां आयोजित की गयी, जिसमें पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव में जुटने का आह्वान किया। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित इस कार्यशाला को प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने संबोधित किया। गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि देश में हालात चिंताजनक है और ऐसी फासीवादी ताकतें जिनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है, वे सत्ता में बैठी हैं जिनका व्यवहार चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि ब्लॉक अध्यक्ष अपने—अपने इलाके के लोगों को पार्टी से जोड़ें व संगठन तथा सरकार के निर्देश उन तक पहुंचाएं। गहलोत ने कहा कि वे सरकार की प्रमुख योजनाओं को भी निचले स्तर तक पहुंचाने का काम करें।डोटासरा ने ब्ल क अध्यक्षों से सात दिन में कार्यकारिणी बनाने को कहा। उन्होंने बाद में मीडिया से कहा, हमारे पास पूरा

संगठन तैयार है। सरकार की अच्छी योजनाएं हैं। हम सब सक्रिय हैं। सब एकजुट हैं। और एकजुटता के साथ चुनाव में जाएंगे और चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा कि , राज्य सरकार ने एक से बढ़कर एक काम किया है और लोगों में कांग्रेस के प्रति उत्साह है और सरकार के प्रति कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है जबकि विपक्षी भाजपा लड़खड़ा रही है अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही है। वहीं पायलट ने अपने संबोधन में कहा की प्रभारी मंत्रियों को जिलों में जाना चाहिए, मंत्री जिला और ब्ल क अध्यक्ष के साथ बैठकें करे। उन्होंने कहा कि पदाधिकारी व कार्यकर्ता आज से ही चुनाव में जुट जाएं। उन्होंने कहा, कोई कह रहा है चुनाव में ६० दिन है कोई कह रहा है १०० दिन है मै कहता हूं कि जीरो दिन है चुनाव का आगाज जब होगा हो जायेगा, आप तो आज ही चुनाव का आगाज कर दो। पूर्व मंत्री हरीश चौधरी भी बैठक में मौजूद थे। उन्होंने ट्वीट किया, पीसीसी मुख्यालय, जयपुर में नवनिर्वाचित ब्ल क अध्यक्षों की एक दिवसीय कार्यशाला में शामिल हुआ। यहां,आगामी चुनावों की रणनीति एवं विभिन्न पदों की जिम्मेदारी पर विस्तार से चर्चा हुई।

अधिवक्ता के चेहरे पर स्टेपलर से हमला, रिपोर्ट दर्ज

लखनऊ। हुसैनगंज थानाक्षेत्र अन्तर्गत विकास दीप बिल्डिंग के समीप दो अधिवक्ता आपस में भिड़ गए। जहां एक अधिवक्ता ने दूसरे अधिवक्ता के चेहरे पर स्टेपलर से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। विरोध किए जाने पर अरोपित अधिवक्ता पीड़ित को जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गया। हालांकि, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अरविंद कुमार विकास दीप बिल्डिंग के रजिस्टार फर्म सोसाइटी एंड चिट्स में अधिवक्ता है। अरविंद के मुताबिक, सोमवार दोपहर ०१रू३० बजे अधिवक्ता मोहम्मद फहद निजी काम के सिलसिले में उनके कार्यालय पर आए थे। आरोप है कि पत्रावली के सम्बन्ध फहद बहसबाजी के साथ असंवैधानिक कार्य का दबाव बनाने लगा। इनकार करने पर दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इस बीच फहद ने अरविंद के चेहरे पर स्टेपलर से हमला कर लहुलुहान कर दिया। अरविंद ने बताया कि वह सरकारी अधिवक्ता हैं। फहद सरकारी कार्यों में बाधा डालते हुए गलत काम कराने का अतिरिक्त दबाव डाल रहा था। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

अश्लील मैसेज भेज विवाहिता को दी जान से मारने की धमकी

लखनऊ। पीजीआई थाने में एक विवाहिता ने शोहदे के खिलाफ लिखित शिकायत देते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। विवाहिता का आरोप है कि कुछ समय से आरोपित उसके वाट्सएप नंबर पर अश्लील मैसेज भेज रहा है। विरोध करने पर आरोपित उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। प्रभारी निरीक्षक राना राजेश सिंह ने बताया कि वृंदावन योजना तेलीबाग की रहने वाली महिला ने शोहदे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। महिला का कहना है कि कुछ समय से वह अपने पति का मोबाइल इस्तेमाल कर रही हैं। उनके वाट्सएप नंबर पर एक युवक लगातार अश्लील मैसेज भेज रहा है। इस पर महिला ने आरोपित का विरोध किया तो वह अलग—अलग नंबरों से क ल कर पैसों की मांग करने लगा। इनकार करने पर आरोपित महिला के परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगा। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। फिलहाल, सर्विलांस की मदद से आरोपित की लोकेशन ट्रेस की जा रही है।

ग्रेटर नोएडा के गैलेक्सी प्लाजा में भीषण आग

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के गैलेक्सी प्लाजा में गुरुवार को भीषण आग लग गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, घटना के बाद लोगों को प्लाजा से बाहर कूदते देखा गया। यह घटना बिसरख पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत गौर सिटी १ में एवेन्यू १ की तीसरी मंजिल पर हुई। सूत्रों के मुताबिक घटना का कारण श र्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग की लपटों से बचने की कोशिश में लोगों को इमारत से कूदते देखा गया। वीडियो में कुछ लोग बिल्डिंग की खिड़की पर लटके लोगों को कूदने के लिए कह रहे हैं। वीडियो में लगभग तीन लोगों को कूदते हुए दिखाया गया है। दमकल गाड़ियों को म ल में भेजा गया, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है। नुकसान की सीमा का तुरंत पता नहीं चल पाया है। अप्रैल में, गौर सिटी २ के १४वें एवेन्यू के एक फ्लैट में लैंप से आग लग गई, जिससे आसपास के फ्लैट भी क्षतिग्रस्त हो गए थे।

दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर, आज रात से पानी कम होने के आसार, लालकिला शुक्रवार को रहेगा बंद

नई दिल्ली। पिछले चार दिनों से लगातार बढ़ रहे यमुना नदी का जलस्तर पिछले तीन घंटे से स्थिर है। गुरुवार को दोपहर एक और दो बजे यमुना का जलस्तर २०८.६२ मीटर था। इसके बाद से स्थिरता बनी हुई है। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्लूसी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर स्थिर हो गया है और यह आज रात से कम होना शुरू हो जाएगा। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण गढ़ी मेंडू गांव के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के बाद हुए जलभराव के कारण कई जगहों पर यातायात के लिए मार्ग बदले गए। इस वजह से भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। क्ष्ळ (छक्त्) मोहसिन शाहिदी ने कहा कि यमुना का जलस्तर २०८.६६ मीटर पर पहुंच गया है। इसके चलते दिल्ली के निचले इलाकों में काफी जगह पानी आ गया है। इन इलाकों में छक्त् की १२ टीमें तैनात की गई थीं। आज हमने अतिरिक्त टीम लगाई हैं जिससे लोगों को तुरंत बचाया जा सके। हालात अभी नियंत्रण में है। मुझे लगता है कि कल तक स्थिति बहुत हद तक बेहतर होगी। क्ब्ल् ने सावधानी लेते हुए इस मार्ग पर मेट्रो की रफ्तार ३० किमी प्रती घंटे तक सीमित किया है। बुधवार को, यमुना में जल स्तर ४५ साल पुराने रिक र्ड को तोड़ते हुए रात ११ बजे २०८.४८ मीटर तक पहुंच गया था। अधिकारियों ने कहा था कि जल स्तर और बढ़ने की संभावना है। दिल्ली सरकार ने रविवार तक सभी स्कूल, क लेज और गैर–जरूरी सरकारी कार्यालय बंद रखने का आदेश दिया है। दिल्ली मेट्रो रेल क पोरेशन (डीएमआरसी) ने नदी के जल स्तर में वृद्धि के कारण ब्लू लाइन पर यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश और निकास अस्थायी

रूप से बंद कर दिया है। पानी की वजह से चुनौतिया अभी बभी मौजूद हैं। मेटकाफ रोड स्थित सुश्रुत ट्र मा सेंटर में बाढ़ का पानी घुस गया। बाढ़ के बीच मरीजों को लोक नायक जय प्रकाश (स्छश्रच) अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। पानी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आ गया है जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इस के चलते कश्मीरी गेट पर भी पानी आ गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली में बाढ़ की स्थिति पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली में लाल किले तक बाढ़ का पानी पहुंचा है। दिल्ली की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूल, क लेज और यूनिवर्सिटी को रविवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। सरकारी स्कूलों को राहत शिविर में तब्दील किया जा रहा है। यमुना में पानी का उफान इस कदर है कि आईटीओ हो या फिर दिल्ली सचिवालय, मयूर बिहार का प श इलाका हो या फिर कश्मीरी गेट, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। दिल्ली सरकार के मंत्री जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। उनकी ओर से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जाने के दावे भी किए जा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के नेता भी जमीन पर मदद पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दिल्ली में जल प्रलय की वजह से जल संकट का भी दौर आ सकता है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि पानी भर जाने की वजह से वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करना पड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पीने के पानी को लेकर दिल्ली में एक–दो दिनों का संकट आ सकता है। पानी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास तक भी पहुंच रहा है।

चरस के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह का सदस्य गिरफ्तार

लखनऊ। चारबाग राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी टीम को ट्रेनों से अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के

एक अभियुक्त को तीन किग्रा चरस के साथ पकड़ने में बड़ी सफलता मिली। अवैध चरस की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब ७ लाख रुपये बताई गयी। अभियुक्त बिहार के बेतिया से चरस को ट्रेन से लेकर लखनऊ बेचने पहुंचा था । गुरुवार को जीआरपी टीम की ओर से चारबाग प्लेटफार्म संख्या ६७ का अन्तिम छोर बाराबंकी साइड पर जांच की जा रही था जहां एक युवक संदिग्ध दिखा जीआरपी जवानों को देखते ही युवक भागने लगा जहां जवानों ने दौड़ाकर युवक को धर दबोचा। युवक की तलाशी के दौरान उसके पास से ८ पैकेट में करीब ३ किग्रा अवैध चरस बरामद हुआ। पूछताछ करने पर युवक ने अपना नाम नन्हे अंसारी पुत्र सुमनेल्लाह अंसारी मिर्जापुर,पूर्वी चम्पारन बिहार का रहने वाला बताया । उसने बताया कि यह चरस वह बेतिया बिहार से ट्रेन से लेकर लखनऊ बेचने आया था जीआरपी ने युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक रेलवे लखनऊ के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की घटनाओ की रोकथाम पर अंकुश लगाने को लेकर जीआरपी की ओर से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस उपाधीक्षक रेलवे लखनऊ संजीव कुमार सिन्हा, चारबाग जीआरपी थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह के नेत्रत्व में गठित टीम रोजाना ट्रेनों व स्टेशन पर चेकिंग कर सघन जांच अभियान चला रही है ।

किसानों के लिये खुशहाली की राह खोलेगा डिजिटल क्रॉप सर्वे : शाही

लखनऊ। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंगलवार को कहा कि एग्री स्टेक (डिजिटल एग्रीकल्चर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर) के तहत डिजिटल क्रॉप सर्वे किसानो के जीवन में खुशहाली की राह खोलेगा। डिजिटल क्राप सर्वे को संपादित कराने के लिये जिला एवं तहसील स्तर के चयनित मास्टर ट्रेनर के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुये श्री शाही

ने कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे में मास्टर ट्रेनर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यह सर्वे किसानों के जीवन में खुशहाली की नई राह खोलेगा। सर्वे के माध्यम से फसलों के जो आंकड़े प्राप्त होंगे, उससे प्रदेश के कृषकों के लिए योजना बनाने में बहुत सुविधा प्राप्त होगी। इन आंकड़ों के आधार पर किसानों के लिए आवश्यक और उपयोगी योजनाओं को तैयार किया जा सकेगा, जो कृषकों के लिए लाभकारी होगा। इसके अतिरिक्त डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से प्राप्त होने वाले आंकड़ों से जहां एक और कृषकों को लाभ प्राप्त होगा, वहीं सरकार और उपभोक्ता सभी इससे लाभान्वित होंगे। उन्होने इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार जताते हुये कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश के विकास पर विशेष ध्यान है। देश के १२ राज्य, जहां डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य पायलट बेस पर किया जा रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश को भी चुना गया है। कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कार्यक्रम में आए प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए उन्हें निर्देशित किया कि यहां बताई गई बातों को ठीक प्रकार से समझकर जिले में सभी सर्वेयर, सुपरवाईजर एवं वैरीफायर्स को ठीक प्रकार से प्रशिक्षण प्रदान करें, जिससे डिजिटल क्रॉप सर्वे का यह अभियान अपनी सफलता प्राप्त कर सके। अपर मुख्य सचिव कृषि डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने एग्री स्टेक के महत्व को समझाते हुए इससे होने वाले लाभ विस्तार से बताए। उन्होंने कहा कि एग्री स्टेक एक डिजिटल फाउंडेशन है जो भारत में कृषि में सुधार के लिए विभिन्न हितधारकों को आसानी से एक साथ लाने और डेटा और डिजिटल सेवाओं का उपयोग करके किसानों के लिए बेहतर योजनाओं का नियोजन, सेवाओं तक कृषकों की सुगम पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किया जा रहा। एग्री स्टेक का निर्माण कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य के साथ मिलकर किया जा रहा है।

सभी स्कूली वाहनों का फिटनेस जांच की जाय, सुरक्षा मानक से न हो खिलवाड़ : सुरेन्द्र कुमार

लखनऊ। परिवहन विभाग के उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र लखनऊ सुरेन्द्र कुमार ने बुधवार को जोन के सभी एआरटीओ प्रशासन अधिकारियों के साथ लखनऊ आरटीओ कार्यालय के एनआईसी सेंटर में बैठक की। उन्होंने बैठक के दौरान कड़ाई से निर्देश देते हुये कहा कि सभी स्कूली वाहनों की चेकिंग कर फिटनेस हर हाल में देखे साथ ही यह सुनिश्चित करायें कि जिन बसों से बच्चों को लाया ले जाया जा रहा है उनमें सुरक्षा के सभी मानक पूरे हैं या नहीं। बसों में मानक पूरे नहीं होने पर संबंधित स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाये जिससे किसी हाल में अप्रिय घटना ना हो। इसके अलावा उप परिवहन आयुक्त ने राजस्व की समीक्षा कर

शत प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने पर जोर देते हुये कहा कि राजस्व वसूली बढ़ाये जाये इसके किसी प्रकार की उदासीनता नहीं बरती जाय। बकाया वसूली के लिए लिस्ट तैयार कर एआरटी ,पीटीओ को उपलब्ध करा दिया जाये जहा वह जिला प्रशासन से समन्वय बनाकर वसूली में तेजी लाये। बैठक में डीटीसी ने स्पष्ट रुप से निर्देश देते हुये कहा कि आरटीओ कार्यालय दलाल मुक्त होना चाहिये किसी प्रकार की शिकायत पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा आरटीओ कार्यालय में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाये। कार्यालय स्वच्छ व साफ होना चाहिये। कार्यालय में आने वाले आवेदकों के लिए पीने का पानी सुनिश्चत करायें।

पुराने बंगले से कितना अलग होगा राहुल का नया आवास, शीला दीक्षित के घर में किराए पर होंगे शिफ्ट

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास आखिरकार अपना खुद का घर हो सकता है और इसका उनकी पार्टी से ऐतिहासिक जुड़ाव है। वायनाड के पूर्व सांसद – उन्हें मोदी उपनाम मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था, वह अपनी मां सोनिया गांधी के साथ राजधानी में उनके १० जनपथ स्थित घर पर रह रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि वह पिछले कुछ समय से एक घर की तलाश में थे। अब ऐसा लगा रहा है कि उनकी तलाश सफल हो गई है। ऐसी खबरें सामने आई हैं कि पूर्व कांग्रेस नेता जल्द ही एक साधारण तीन बेडरूम वाले घर में रहने वाले हैं और यह किसी और का नहीं बल्कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का है, जिन्होंने अपने जीवन के आखिरी साल वहां बिताए थे। राहुल गांधी दक्षिण दिल्ली के हरे–भरे निजामुद्दीन पूर्वी इलाके में हुमायूँ के मकबरे के नजदीक १,५०० वर्ग में फैले तीन–बीएचके आवास में शिफ्ट हो सकते हैं। यह घर दिग्गज कांग्रेस नेता शीला दीक्षित के परिवार का है, जो १९९१ से १९९८ तक वहां रही। २०१५ के बाद वह फिर से उसी फ्लैट में शिफ्ट हो गईं और २०१६ में उनका वहीं निध ान हो गया। दीक्षित ने १९९१ में यह घर खरीदा था और अपने केरल गवर्नर कार्यकाल के तुरंत बाद वह इसमें रहने लगीं। संयोग से, यह घर १३वीं सदी के सूफी संत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह से कुछ सौ मीटर की दूरी पर है, जहां राहुल ने दिसंबर के आखिरी सप्ताह में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली में प्रवेश करने पर प्रार्थना की थी। दिवंगत शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने हाल ही में बाहर जाने की एक अनौपचारिक सूचना दी थी और इसने राहुल के कार्यालय का ध यान आकर्षित किया। सूत्रों ने कहा कि राहुल कई बार घर का दौरा कर चुके हैं और किराए पर आवास लेने के इच्छुक हैं क्योंकि संदीप उसी पड़ोस में दूसरे घर में चले गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के बाद, राहुल १० जनपथ स्थित अपनी मां के आवास को अलविदा कहकर उस घर में चले जाएंगे। अप्रैल में कांग्रेस नेता को १२ तुगलक लेन स्थित उनके विशाल और शानदार आवास को खाली करने के लिए कहा गया था। ऐसा तब हुआ जब गुजरात में मोदी उपनाम मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण उन्हें संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अयोग्य ठहराए जाने के तुरंत बाद लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने राहुल गांधी को बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया था।

जिस घर को वह दो दशकों तक अपना घर कहते थे, उसे छोड़ते समय राहुल गांधी ने कहा था, "मैं सच बोलने की कीमत चुका रहा हूं।" उन्होंने बंगले के बाहर पत्रकारों से आगे कहा, भले ही यह मुझसे छीन लिया गया हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।श यह घर मुझे भारत के लोगों ने दिया था।' मैं कुछ समय के लिए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष (सोनिया गांधी) के साथ १०, जनपथ पर रहूंगा और फिर कोई दूसरा रास्ता ढूंढूंगा। २००४ के आम चुनाव में अमेठी लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल करने के बाद राहुल को यह टाइप VIII बंगला आवंटित किया गया था। टाइप VIII बंगले सांसदों और मंत्रियों को आवंटित आवासों में सबसे अधिक मांग वाले हैं और ये दिल्ली के पॉश इलाकों जैसे अशोक रोड, लोधी एस्टेट, कुशक रोड, कैनिंग लेन, तुगलक लेन आदि में स्थित हैं।

कांग्रेस ने मोदी सरकार पर मंत्रालयों के प्रचार फंड को केंद्रीय संचार ब्यूरो को सौंपने का लगाया आरोप

नई दिल्ली। कांग्रेस ने गुरुवार को मोदी सरकार पर प्रचार के लिए संसद द्वारा विभिन्न मंत्रालयों को आवंटित ४० प्रतिशत धनराशि हड़पने और उसे केंद्रीय संचार ब्यूरो को सौंपने का आरोप लगाया और पूछा कि क्या यह दुरुपयोग नहीं है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि ऐसा करके सरकार ने संसद द्वारा पारित बजट की पवित्रता को कम कर दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार को पीएम मोदी के अधीन केंद्रीय प्रचार मशीन भी करार दिया। उन्होंने कहा कि संसद भारत सरकार के सभी विभागों और मंत्रालयों के लिए बजट पर मतदान करती है और प्रत्येक कार्यक्रम/योजना का एक अलग बजट प्रमुख होता है। रमेश ने कहा कि एक अभूतपूर्व कदम में, वित्त मंत्रालय ने १६ मई को आदेश दिया कि विभिन्न विभागों या मंत्रालयों में शविज्ञापन और प्रचारश के लिए संसद द्वारा मतदान किए गए धन का ४० प्रतिशत केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) के निपटान में रखा जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय के आदेश को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि संसद द्वारा अनुमोदित २०२३–२४ के लिए सीबीसी का बजट २०० करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय के १६ मई के आदेश से चालू वर्ष के लिए सीबीसी का बजट बढ़कर ७५० करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि स्पष्ट रूप से यह सीबीसी (सीबीआई और ईडी के साथ) २०२४ के लिए मोदी

सरकार के चुनाव अभियान का अगुआ होगा। सीबीसी 'पीएम उर्फ प्रचार मंत्री' की धुन पर नाचने वाला एक श्सुपर जारश है। लेकिन इस प्रचार मशीन के पास पर्याप्त धन नहीं था। जयराम रमेश ने ट्विटर पर पूछा कि अब इस सर्जिकल स्ट्राइक के साथ, कर्नाटक में सरकार द्वारा हटाए गए ४० प्रतिशत कमीशन की तरह, मोदी सरकार ने संसद द्वारा मंत्रालयों को पहले से आवंटित धन का ४० प्रतिशत हड़प लिया और सीबीसी को समृद्ध किया। क्या यह वास्तव में दुरुपयोग नहीं है?

सीमा गुलाम हैदर की हरकतों से बढ़ रहा है शक

लखनऊ। पाकिस्तान से अपने चार बच्चों के साथ भागकर अपने प्रेमी के पास भारत आई सीमा गुलाम हैदर को इन दिनों खूब उपहार मिल रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के जिस घर में वह अपने प्रेमी सचिन के साथ रह रही है वहां उसे आशीर्वाद देने और उपहार देने तथा उससे मुलाकात करने और उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए लोगों की भीड़ लग रही है। सुबह से शाम तक सज धज कर सीमा लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही है। वह रातोंरात किसी सेलेब्रेटी जैसा दर्जा हासिल कर चुकी है। लेकिन धीरे–धीरे उसकी कहानी में नया ट्विस्ट भी आने लगा है। दरअसल, सीमा और सचिन का कहना है कि उन दोनों की मुलाकात २०२० में पबजी पर गेम खेलते हुए हुई थी और बाद में व ट्सएप वीडियो क ल पर उन दोनों की बातें होने लगी थीं। लेकिन पबजी पर भारत में २०२० में ही प्रतिबंध लग गया था। हालांकि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) का इस्तेमाल कर इस प्रतिबंधित अ नलाइन गेम को अब भी खेला जाता है। इसके अलावा इस बात पर भी शक जा रहा है कि क्यों सीमा ने अपनी सारी चौट हिस्ट्री डिलीट की। हम आपको बता दें कि गिरफ्तारी के समय पुलिस ने सीमा हैदर के पास से चार फोन बरामद किये

थे और चारों में से किसी की भी चौट हिस्ट्री उपलब्ध नहीं थी। एक फोन तो टूटा हुआ भी मिला था। इसके अलावा लोगों का शक इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि एक ओर सीमा बताती है कि वह बस पांचवीं कक्षा तक पढ़ी है लेकिन उसके पास हर सवाल का जवाब होता है। इसके अलावा चंद दिनों में वह जिस तरह हिंदू रीति रिवाजों और भारतीय परिवेश में ढल चुकी है वह भी आश्चर्य पैदा कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसे पहले से ही सभी चीजों की जानकारी थी या उसने इसके पूर्वाभ्यास किया था। ऐसे में उसके पाकिस्तानी जासूस होने पर शक बढ़ता जा रहा है। हम आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियां सीमा से पूछताछ कर चुकी हैं फिर भी अभी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। सीमा को अभी भारत आये कुछ ही दिन हुए हैं लेकिन वह शुद्ध हिंदी बोलती है। उसकी बोली में कहीं उर्दू का इस्तेमाल नहीं होता। ऐसे में सवाल उठता है कि भले उसने देश छोड़ दिया हो लेकिन बोली और लहजा इतनी जल्दी कोई कैसे छोड़ सकता है? वहीं जिस तरह आसानी से सीमा नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश कर गयी उस पर भी सुरक्षा एजेंसियां अचरज में हैं। वैसे जिस इलाके में सीमा और सचिन रहते हैं उस इलाके में लोगों को पाकिस्तानी महिला के रहने पर कोई आपत्ति नहीं है। एक ओर जहां सीमा का पति गुलाम हैदर वीडियो जारी कर भारत सरकार से मांग कर रहा है कि उसकी पत्नी को वापस भेजा जाये वहीं ग्रेटर नोएडा के रबुपूरा के लोगों का कहना है कि सीमा और उसके बच्चों की इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए। यदि वह वापस नहीं जाना चाहते तो उन्हें यहां रहने देना चाहिए। इस बीच, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीमा हैदर को लगातार पाकिस्तान से धमकी मिल रही हैं। पाकिस्तान से आई एक नई धमकी में कहा गया है कि यदि भारत ने सीमा हैदर और उसके चारों बच्चों को जल्द ही पाकिस्तान वापस नहीं भेजा तो पाकिस्तान में मंदिरों और हिंदुओं को निशाना बनाया जायेगा। इससे पहले भी एक मीडियाकर्मी को पाकिस्तान से भेजे गये व इस संदेश में सीमा को धमकी दी गयी थी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, सीमा को पाकिस्तान से जो ताजा धमकी मिली है उसमें कहा गया है कि सीमा का इस तरह से जाना पूरी तरह इस्लाम के खिलाफ है। ध मकी में कहा गया है कि यदि सीमा और उसके बच्चे पाकिस्तान वापस नहीं आये तो सिंध के कच्छ में घोटकी हिंदू मंदिर पर हमला होगा और हिंदुओं को निशाना बनाया जायेगा। इस धमकी के बारे में सीमा ने पाकिस्तानी जनता से अपील की है कि वह हिंदुओं की सुरक्षा करें। सीमा ने स्पष्ट किया है कि वह सचिन को छोड़कर किसी हालत में पाकिस्तान नहीं जायेगी। उसका कहना है कि उसके भारत आने के बाद पाकिस्तान में धर्म को मुद्दा बनाया जा रहा है। सीमा ने कहा है कि उसके प्यार को हिंदू मुस्लिम लड़ाई का रंग नहीं देना चाहिए। दूसरी ओर, एआईएमआईएम पार्टी के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सीमा अपना धर्म कैसे बदल सकती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है ऐसे में सीमा ने धर्म कैसे बदल लिया। उन्होंने पूछा कि क्या यह लव जिहाद नहीं है?

छह वर्ष में छह लाख युवाओं को दी गई नौकरी, विभागों में हो रही नियुक्तियां : योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश देश का सबसे युवा राज्य है। यहां के युवाओं की प्रतिभा का लाभ दिलाने के लिए उन्हें रोजगारध्नौकरी उपलब्ध कराना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ध्येय है, इसलिए योगी सरकार ने पिछले छह वर्ष में छह लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी। यही नहीं, सिर्फ बीते एक महीने पर नजर दौड़ाएं तो उत्तर प्रदेश के ११ हजार से अधिक युवाओं को सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र सौंपा। एक महीने में ११ हजार से अधिक नौकरी देकर योगी सरकार ने यह बता दिया कि युवा उनकी प्राथमिकता में हैं। २०१७ के बाद से सिर्फ पात्रता ही चयन का आधार बना और इस शुचिता व निष्पक्षता के सभी कायल भी हुए। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित ११४८ पदों पर उपनिरीक्षकों को ६ जुलाई को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इन पदों में ५८७ पद सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक), २१७ उपनिरीक्षक (गोपनीय), ३४४ सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) शामिल हैं। ठीक दो दिन बाद ८ जुलाई को खिलाड़ी कोटे में चयनित २२७ आरक्षियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। पिछले छह वर्षों में सिर्फ यूपी पुलिस विभाग में ही योगी सरकार की ओर से डेढ़ लाख से अधिक पदों पर भर्तियां की गई है। मृतक आश्रित के रूप में २५०० भर्तियां अतिरिक्त की गईं। सुरक्षा के ष्टिगत पुलिस विभाग में यह भर्तियां काफी तेजी से हो रही हैं। वहीं सरकार ने खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करते हुए सरकारी नौकरी से जोड़ा। कई खिलाड़ियों को राजपत्रित नौकरी दी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ का मानना है कि स्वास्थ्य व शिक्षा

के क्षेत्र में यूपी को काफी समृद्ध करना है, इसलिए इन दोनों क्षेत्रों में न सिर्फ अभूतपूर्व कार्य हुए, बल्कि जून में ही सीएम योगी ने ७१८२ एएनएम स्वास्थ्य कार्यकत्रियों और एसजीपीजीआई में नवचयनित १४४२ स्ट फ नर्सों को भी नियुक्ति पत्र दिया। यही नहीं, नियुक्ति के साथ सीएम योगी ने समय–समय पर युवाओं को सम्मान भी दिया। ६ जून को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में संघ लोकसेवा आयोग में २३ व उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग में ६५ चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान समारोह भी आयोजित कर इन्हें गौरवान्वित किया गया। कोरोना काल में जब रफ्तार थम गई थी, तब भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। पिछले पांच वर्ष में लगभग तीन करोड़ लोगों को भी रोजगार दिया गया। साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) के जरिए रोजगार व नौकरी के एक करोड़ नए अवसर भी मुहैया कराने को योगी सरकार संकल्पित है। पहली बार है जब सभी ७५ जनपदों में निवेश के अवसर उपलब्ध कराए गए। योगीराज में लगभग सवा लाख से अधिक महिलाओं को सरकारी नौकरी मिली। योगी सरकार ने नई एमएसएमई नीति–२०२२ लागू की। २.३५ लाख करोड़ की वार्षिक ऋण योजना प्रारंभ की। ओडीओपी–ई क मर्स पोर्टल पर लगभग २१ हजार से अधिक उत्पादों की बिक्री की गई। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से भी तकरीबन डेढ़ लाख रोजगार सृजित किए गए। कौशल विकास मिशन में विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षित करीब १०.२० लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिलाए गए।

वेबसाइट बनाकर फर्जी आधार-पैनकार्ड बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार

लखनऊ। फर्जी वेबसाइट बनाकर जाली आधार कार्ड व पैन कार्ड बनाने वाले शातिर अंतर्राज्यीय गिरोह का साइबर पुलिस ने भण्डाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जिनकी पहचान बिहार के पूर्वी चम्पारण निवासी अफजल आलम, गया निवासी मो. इरशाद व अमेठी निवासी सुशील कुमार के रूप में हुई है। आरोपियों के पास से पुलिस ने १०३ फर्जी आधार कार्ड, तीन फर्जी पैन कार्ड, १२० से अधिक एंड्र यड व कीपैड वाले मोबाइल फोन आदि सामान बरामद किया है। वहीं इस गिरोह के ६ सदस्यों को पुलिस पूर्व में ही गिरफ्तार कर चुकी है। मामले की जानकारी देते हुए साइबर एसपी, यूपी प्रो. त्रिवेणी सिंह ने बताया कि वाराणसी में दर्ज हुए इस मुकदमे में पुलिस ने बिहार से गिरोह के चंदन यादव व विजय यादव को गत ७ मई को गिरफ्तार किया था। ये दोनों आरोपी फर्जी आधार कार्ड व पैन कार्ड से देश के विभिन्न राज्यों में फर्जी बैंक खाते खोलने व फर्जी मोबाइल सिम एक्टिवेट कराने का काम करते थे। इसी गिरोह द्वारा विभिन्न साइबर अपराधियों को भी बैंक डिटेल व मोबाइल सिम उपलब्ध कराये जा रहे थे। जांच में पता चला कि इनके बैंक खाता खोलने व सिम खरीदने के लिए डिजिटल पोर्टल डॉट इन नामक वेबसाइट से फर्जी आधार कार्ड व पैन कार्ड बनाये जाते हैं। जांच करने पर वेबसाइट के लिए काम करने वाले पंकज यादव की २४ जून को बिहार से गिरफ्तारी हुई। पंकज से पूछताछ में पता चला कि फर्जी आधार व पैन कार्ड बनाने वाली कई वेबसाइट संचालित हैं। पंकज की निशानदेही पर अफजल, इरशाद और सुशील को गिरफ्तार किया। एसपी त्रिवेणी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पता चला कि उन्होंने डोमेन प्रोवाइडर से डोमेन खरीदकर इस प्रकार की नौ वेबसाइट बनाई थीं। जिनमें एपीआई बनाकर डाटा फिशिंग (डाटा चुराना और बेचना) की जाती थी। इन वेबसाइट में कोई भी व्यक्ति लॉग इन करके ऑनलाइन फिंगरप्रिंट देकर व मैनुअल डाटा भरकर अपना आधार, पैन या किसी तरह का आईडेंटिटी प्रूफ बना सकता था। पर आधार या पैन को प्रिंट करने के लिए शुल्क अदा करना पड़ता था। इसी दौरान वेबसाइट से ऑनलाइन फिंगर प्रिंट करते ही स्वतः ही आवेदक का सारा डाटा डोमेन में सेव हो जाता था, जिससे फर्जी आधार व पैन कार्ड आदि बनाये जाते थे। एसपी त्रिवेणी ने बताया कि पेमेंट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर से मिली जानकारी के अनुसार इन वेबसाइट्स पर प्रत्येक आधार कार्ड को प्रिंट करने के लिए २० रुपये व पैन कार्ड के लिए १६ रुपये शुल्क लिया जाता था। सिर्फ एक वेबसाइट्स से प्रतिदिन एक–एक हजार फर्जी आधार कार्ड व फर्जी पैन कार्ड छापे जाते थे। यानी सालाना करीब ४ लाख आधार व ४ लाख पैन कार्ड की प्रिंटिंग होती थी। जिससे एक ही वेबसाइट से गिरोह को सालाना ७५–८० लाख रुपये की कमाई हो जाती थी। यानी ६ वेबसाइट्स से सालाना साढ़े छह से सात करोड़ रुपये की आमदनी होती थी। एसपी त्रिवेणी ने बताया कि पकड़ा गया अभियुक्त मो. इरशाद पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वह कई सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनियों में बतौर प्रोग्रामर नौकरी कर चुका है। इरशाद ही इन सभी ६ वेबसाइट्स की देखरेख करता था और वेबसाइट में कोई भी समस्या होने पर उसका निराकरण करता था। इरशाद के सिक्योरिटी सिस्टम के कारण ही पिछले काफी समय से संचालित होने के बावजूद इन वेबसाइट्स को ट्रैक नहीं किया जा पा रहा था।

मानसून सत्र से पहले कांग्रेस की बैठक, १६ जुलाई को सोनिया गांधी के आवास पर बनेगी रणनीति

नई दिल्ला। संसद के आगामी मानसून सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा के लिए कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक १६ जुलाई को यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर होने

वाली है। पार्टी सूत्रों ने इस बात को लेकर बड़ी जानकारी दी है। यह बैठक १७–१८ जुलाई को कर्नाटक के बेंगलुरु में कांग्रेस द्वारा बुलाई जा रही दूसरी विपक्षी एकता बैठक से ठीक एक दिन पहले होगी। सूत्रों ने कहा कि १६ जुलाई की बैठक में २० जुलाई से शुरू होने वाले आगामी संसद सत्र में सबसे पुरानी पार्टी द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें मणिपुर हिंसा, बढ़ती मुद्रास्फीति और बेरोजगारी शामिल है। मानसून सत्र ११ अगस्त तक चलने वाला है। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें गुजरात उच्च न्यायालय के हालिया आदेश पर भी चर्चा होगी, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'मोदी उपनामष टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है। गुजरात भ्ब अदालत ने ८ जुलाई को सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा और राहुल गांधी को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। कांग्रेस नेता ने २५ अप्रैल को सूरत सत्र अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसने आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सूरत सत्र अदालत ने २० अप्रैल को आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने की राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी। कांग्रेस पार्टी मणिपुर हिंसा, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, रेलवे सुरक्षा, देश के संघीय ढांचे पर हमला आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने का फैसला कर सकती है। इससे पहले पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा था कि समान नागरिक संहिता पर कांग्रेस नेता ने कहा, पार्टी ने १५ जून को ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने कहा, 'चूंकि पिछले १५ दिनों के दौरान इस मामले पर कुछ भी नया नहीं आया है, इसलिए पार्टी के पास अभी इसमें जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है।'

मसाला डोसा के साथ सांभर नहीं देना बिहार के रेस्टोरेंट को पड़ा महंगा, लगा ३५०० का जुर्माना

पटना। बिना सांभर के डोसे का कोई क म्बिनेशन भला कैसे हो सकता है! लेकिन बिहार के एक रेस्टोरेंट में सारा कांड उस सांभर को न देने की वजह से हुआ। १४० रुपये में मसाला डोसा बेचने पर रेस्टोरेंट को अब ३,५०० रुपये का जुर्माना देना होगा। लेकिन क्यों?

१५ अगस्त २०२२ की घटना की वजह से, इसी दिन मनीष गुप्ता नाम के वकील का जन्मदिन था। वह अपने जन्मदिन पर मसाला डोसा खाना चाहते थे। उन्होंने बिहार के बॉक्सर में एक रेस्तरां में मसाला डोसा का अ र्डर दिया। जिसकी कीमत १४० रुपये थी। बाद में वकील ने देखा कि डोसा के साथ सांबर नहीं है। यह देखकर वो हैरान रह गए। रेस्टोरेंट से संपर्क किया। रेस्टोरेंट के अधिकारी इस बात का कोई जवाब नहीं दे सके कि डोसे के साथ सांभर क्यों नहीं परोसा गया। बल्कि रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा, श्श्क्या आप १४० टका में पूरा रेस्टोरेंट खरीदना चाहते हैं? जिसके बाद वकील ने इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़नी की ठानी। रेस्टोरेंट को कानूनी नोटिस दिया। लेकिन रेस्टोरेंट की ओर से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद मनीष ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करायी। करीब ११ महीने बाद उपभोक्ता आयोग की खंडपीठ ने रेस्टोरेंट को दोषी करार दिया। साथ ही आयोग ने ३ हजार ५०० रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता मनीष गुप्ता को हुई मानसिक, शारीरिक और आर्थिक पीड़ा पर ध्यान दिया। जिसके बाद रेस्तरां पर ३,५०० रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना दो भागों में लगाया गया मुकदमेबाजी लागत के रूप में १,५०० रुपये और मूल जुर्माना के रूप में २,००० रुपये। कोर्ट ने कहा कि अगर समय पर भुगतान नहीं किया गया तो जुर्माना राशि पर रेस्तरां को ८ फीसदी ब्याज भी देना होगा।

तीन माह में १८ 'सेफ सिटी' वाला देश का पहला राज्य होगा उत्तर प्रदेश : मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी १७ नगर निगमों और गौतमबुद्ध नगर को 'सेफ सिटी' (सुरक्षित शहर) के रूप में विकसित करने के निर्देश देते हुए मंगलवार को कहा कि अगले तीन महीनों के अंदर उत्तर प्रदेश १८ सेफ सिटी वाला देश का पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर प्रदेश में 'सेफ सिटी' परियोजना के विस्तार की कार्ययोजना का जायजा लिया। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने यहां बताया कि आदित्यनाथ ने पहले चरण में राज्य के सभी १७ नगर निगमों और गौतमबुद्ध नगर को सेफ सिटी के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि अगले तीन माह के अंदर पहले चरण का काम पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि पहले चरण के कार्य के दौरान संबंधित विभाग को दी गई जिम्मेदारी तय समय सीमा के अंदर पूरी की जाए और मुख्य सचिव इसकी पाक्षिक समीक्षा करें। आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस परियोजना के दूसरे चरण में ५७ जनपद

मुख्यालयों की नगर पालिकाओं और तीसरे चरण में १४३ नगर पालिकाओं को 'सेफ सिटी' परियोजना से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी नगरों के प्रवेश द्वार पर सेफ सिटी का बोर्ड लगाकर इसकी 'विशिष्ट ब्रांडिंग' भी की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेफ सिटी परियोजना महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित है।इसे विस्तार देते हुए बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांगजनों की सुरक्षा से भी जोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से प्रदेश में लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत आधुनिक नियंत्रण कक्ष, पिंक पुलिस बूथ, आशा ज्योति केंद्र, सीसीटीवी कैमरे, महिला पुलिस थानों में परामर्शदाताओं के लिए सहायता डेस्क, बसों में 'पैनिक बटन' और अन्य सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे। इस परियोजना के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों व दिव्यांगजनों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित एवं सशक्त वातावरण बनाने की मुहिम को आवश्यक तेजी मिलेगी। आदित्यनाथ ने कहा कि सेफ सिटी पोर्टल को भी विकसित किया जाए। इससे ऐसे सभी विभागों को जोड़ा जाए, जिनके द्वारा महिला, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के हित में कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

'चंदू चौंपियन' की शूटिंग शुरू, कार्तिक आर्यन ने कबीर खान के साथ शेयर की तस्वीर

मुम्बई। 'भूल भुलैय' की सफलता के बाद से बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन का करियर ग्राफ एक नए स्तर पर पहुंच गया है। अभिनेता एक के बाद एक फिल्मों में नजर आ रहे हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हो रही हैं। कार्तिक की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म श्सत्यप्रेम की कथाश ने कुछ दिनों पहले ही १०० करोड़ की कमाई का आकंड़ा पार किया है। इसी के साथ ये फिल्म इस साल की हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है। 'सत्यप्रेम की कथा' अभी भी बॉक्स ऑफिस अपना जादू बिखेर रही है। इन सब के बीच कार्तिक ने अपनी नई फिल्म 'चंदू चौंपियन' की शूटिंग शुरू कर दी है। इस बात की जानकारी अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर दी। कार्तिक आर्यन ने १२ जुलाई को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर निर्देशक कबीर खान एक तस्वीर साझा की। इस तस्वीर में, कबीर अपने हाथ में क्लैपर बोर्ड लेकर बैठे हुए हैं, जिसमें 'चंदू चौंपियन' के पहले टेक की जानकारी है। कार्तिक उनके साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने

इस पोस्ट के साथ अभिनेता ने कैप्शन में एक नोट लिखा और बताया कि ये उनके करियर की सबसे चुनौतीपूर्ण जर्नी है। कैप्शन में कार्तिक ने लिखा, श्शुभारंभ... मेरे करियर की सबसे चुनौतीपूर्ण और रोमांचक यात्रा शुरू होती है... कप्तान **@KabirKhankk** के साथ **#**चंदूचौंपियन।'

हमारे अन्य प्रतिनिधि

lt; ckt ibZ

lhrkiqj

eks-9935160370

प्रियंका त्रिपाठी

नई दिल्ली

विधिक सलाहकार

lqjs'k ukjk;.k feJ

क्षेत्रीय सम्पादक

lkjHk dqekj] fcgkj

eks-09386075289

मो० अरशद

C;wjks phQ

eऊ

कश्मीर की बर्फीली वादियों में साड़ी पहनकर शूटिंग करना नहीं था आसान, आलिया भट्ट ने व्लॉग में किया खुलासा

मुम्बई। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक व्लॉग शेयर किया है, जो फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' के गाने 'तुम क्या मिले' की शूटिंग के दौरान बनाया गया है। बता दें, इस गाने की शूटिंग कश्मीर में हुई है। आलिया ने कश्मीर के माइनस डिग्री तापमान में साड़ी पहनकर गाने की शूटिंग की थी। खास रही है कि ये गाना उन्होंने राहा के जन्म के बाद शूट किया था और वापस शेप में आने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है। उन्होंने अपने वर्कआउट सेशन की झलक दिखाई। इसके अलावा व्लॉग में मनीष मल्होत्रा और करण जौहर को गाने की शूटिंग के दौरान बातचीत करते देखा जा सकता है। व्लॉग में अंत में, करण और

बात यह है कि अभिनेत्री ने माँ बनने के कुछ महीनों बाद इस गाने को शूट किया था। इस बात का खुलासा करण जौहर ने गाने की रिलीज के दौरान किया था। गाने के लिए वापस फिगर में लौटने के लिए आलिया ने काफी मेहनत की है। अभिनेत्री ने व्लॉग में अपने वर्कआउट सेशन की झलक दिखाई है। आलिया भट्ट का व्लॉग 'तुम क्या मिले' गाने की शूटिंग के लिए कश्मीर जाने से शुरू होता है। इसके बाद अभिनेत्री ने अपने व्लॉग में वहां के माइनस तापमान में शूटिंग करने की झलक शेयर की है। इन सब के बीच आलिया बता आलिया को गाड़ी में बैठे बात करते देखा जा सकता है। करण बता रहे हैं कि उन्होंने लगभग १७ साल के बाद सिफॉन साड़ी में कोई गाना शूट किया है। ये आसान नहीं था। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी २८ जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म से करण जौहर फिर से निर्देशक के तौर पर वापसी कर रहे हैं। फिल्म में आलिया भट्ट और रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इन दोनों के अलावा बॉलीवुड दिग्गज कलाकार जैसे जया प्रदा, शबाना आजमी और धर्मेंद्र भी फिल्म में अहम भूमिका में हैं।

अक्षय कुमार को झटका, सेंसर बोर्ड ने ओह माय गॉड २ को नहीं दी हरी झंडी

मुम्बई। आदिपुरुष जैसी प्रतिक्रिया से बचने के लिए, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ओह माय गॉड २ (ओएमजी २) के संवादों और श्यों पर विचार कर रहा है। आगामी फिल्म अक्षय कुमार और परेश रावल की २०१२ की फिल्म ओएमजी— ओह माय गॉड का सीक्वल है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार, बोर्ड की पुनरीक्षण समिति यह सुनिश्चित करना चाहती है कि ओएमजी २ के संवाद और दृश्य 'कोई समस्या पैदा न करें'। और बोर्ड की पुनरीक्षण समिति षफिल्म के संवादों और श्यों पर गौर करने के बाद अक्षय कुमार—अभिनीत ओह माय गॉड २ पर निर्णय लेगी। सीबीएफसी ने अब ओह माई गॉड २ के संवादों और श्यों पर किसी भी प्रतिक्रिया से बचने के लिए ष्पूर्वव्यापी उपायष किए हैं। इससे पहले अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम अभिनीत बहुप्रतीक्षित फिल्म ओह माय गॉड २ ने सिनेमा प्रेमियों के बीच उत्साह पैदा कर दिया है।

ओह माई गॉड २ के किन दृश्यों या संवादों ने सीबीएफसी को चिंता में डाल दिया है, इस बारे में अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। एक बार जब फिल्म पुनरीक्षण समिति के पास जाएगी, तो सीबीएफसी कथित तौर पर फिल्म पर निर्णय लेगा, जो ११ अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। बताया जा रहा है कि सीबीएफसी उस आलोचना को दोहराना नहीं चाहता है जो आदिपुरुष को अपने संवादों को लेकर झेलनी पड़ी थी' ओएमजी २ का टीजर आखिरकार रिलीज कर दिया गया था। टीजर शानदार लग रहा है और यह आपको मंत्रमुग्ध भी कर देगा। जहां ओएमजी का निर्देशन उमेश शुक्ला ने किया था, वहीं फिल्म के दूसरे भाग का निर्देशन अमित राय ने किया है। टीजर में पंकज त्रिपाठी, अक्षय कुमार और यामी गौतम द्वारा निभाए गए किरदारों की झलक मिलती है। भगवान के रूप में कुमार की दमदार एक्टिंग दिख रही है।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, 40 वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी 2/379 रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ0प्र0 से प्रकाशित।

आर.एन.आई UPHIN/2010/32566

सम्पादक

आरती पाण्डेय

मो.9415087228

9889745884. 9807059191. 9026560178

Email- adbhutsamachar@yahoo.in adbhut_samachar@rediffmail.com

सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

समाचार पत्र में छपी समस्त प्रकार की खबरों एवं लेखों का स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्र में छपी खबर एवं लेख पत्रकारों के अपने निजी विचार हैं। समाचार पत्र से जुड़े समस्त पत्रकारों के पद अवैतनिक हैं। और वह सब स्वतंत्र पत्रकार हैं। प्रकाशक/सम्पादक